साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 17-23 फरवरी 2025 वर्ष-10, अंक-44

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

देवास में सीएम मोहन ने जारी की 11वीं किस्त, किसानों के खातों में भेजे गए 1624 करोड़, कहा

मप्र सरकार 2600 रु क्विंटल खरीदेगी गेहूं

जागत गांव हमार, भोपाल।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने देवास के सोनकच्छ के ग्राम पीपलरांवा से एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खाते में 1553 करोड़, 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खाते में 337 करोड़ और 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ सिंगल क्लिक से अंतरित किए। इसके साथ ही सीएम ने 144.84 करोड़ लागत के 53 कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रंजीत सागर परियोजना से आस-पास के गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। क्षेत्र में हरियाली छायेगी और किसान समृद्ध होगा। पारस पत्थर से लोहा भी सोना बन जाता है। हर खेत को पानी और बिजली की सुविधा मिले तो किसान समृद्धशाली होंगे और फसलरूपी सोना जरूर मिलेगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी और बिजली उपलब्ध करा रही है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई ने 20 वर्ष पहले जो नदी जोड़ो का सपना देखा था आज वह प्रदेश में पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने हमें केन-बेतवा लिंक योजना के लिए 1 लाख करोड रुपए दिए हैं। इस योजना से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। एक अन्य 70 हजार करोड रुपए की पार्वती-कालीसिंध-चंबल योजना पर भी कार्य शुरू हुआ है। प्रदेश के प्रत्येक के गांव, एक-एक खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस बार किसानों के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य होगा 2600 रुपए होगा। मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देना है।

गरीबों और किसानों के लिए लगातार काम कर रही सरकार

सीएम ने कहा कि मप्र सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं एवं महिलाओं की बेहतरी के लिए लगातार काम रही है। प्रदेश में महिलाओं, किसानों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के कल्याण के लिए प्रदेश में आगे बढ़कर कार्य किया जा रहा है। समारोह में 1 लाख 27 करोड़ लाड़ली बहनों, 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों, 81 लाख किसानों को 2054 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से प्रदान की गई। प्रदेश सरकार योजनाओं के संचालन में कोई कमी नहीं रहने देगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास का कारवां चल रहा है। दुनिया में भारत का मान-सम्मान बड़ा है। हमें मध्यप्रदेश को नंबर वन बनाना है। हमारी सरकार का संकल्प है हर व्यक्ति की बेहतरी, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी मिले। हम इस दिशा में तेज गति कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रणजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना से गत 2 जनवरी को जलाभिषेक यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो आज यहां संपन्न हो रही है। पहले इस योजना से 52 गांव डूब में आ रहे थे और अब 66 गांवों को पानी मिलेगा। यह हमारी नीति है, हर व्यक्ति की बेहतरी हो, किसी को नुकसान न हो।

जल कलश यात्रा का समापन

समारोह में मुख्यमंत्री ने पार्वती, कालीसिंध एवं चंबल नदी के पानी को घड़े में मिलाकर जल कलश यात्रा का समापन किया। ग्राम भंवरासा से 2 जनवरी को कलश यात्रा से जलाभिषेक अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन हुआ। जल कलश यात्रा में तीनों नदियों के जल को एकत्रित किया गया और समापन पर तीनों नदियों के जल को एक घड़े में मिलाकर इसे रंजीत सागर डेम में प्रवाहित किया जाएगा। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के कार्य रिकॉर्ड स्तर पर संपादित हुए हैं। प्रदेश में साथबर तहसील के कारण अब 20 दिन में नामांतरण और 30 दिन में सीमांकन का कार्य संपन्न हो रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संचालन किया जा रहा है।

अब तक भेजे 14 हजार करोड़

मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार किसानों के खातों में अब तक 14 हजार 254 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। 2024-25 में योजना के लिए 4 हजार 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना का कहना है कि केंद्र और राज्य शासन की ओर से किसानों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक जरूरत को पूरा करना है, ताकि वह कृषि कार्यों के लिए जरूरी वस्तुएं खाद-बीज या कृषि उपकरण खरीद सकें।

अब पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे मिलेंगे

मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 6 हजार सालाना और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6 हजार सालाना मिलते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के किसान हर साल 12 हजार की आर्थिक मदद का लाभ उठाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी होगी। पीएम मोदी बिहार के भागलपुर से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए की 19वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेंगे।

दावा-रंग के साथ-साथ मिनरल्स से भी है भरपूर

अब नारंगी व बैगनी रंग की गोभी भी देखने को मिलेगी

सागर में लाल-पीली गोभी से महक रही पोषण वाटिका

जागत गांव हमार, सागर।

गोभी का फूल एक प्रचलित और लोकप्रिय सब्जियों में गिनी जाती है। भारतीय समाज की शायद ही ऐसी कोई रसोई हो, जहां इसका प्रयोग न होता हो। गोभी को सलाद के रूप में, सब्जी बनाकर, पराठे बनाकर और सूप निकालकर इसका स्वाद लिया जाता है। अभी तक आपने गोभी का कलर सफेद देखा होगा, गोभी की एक प्रजाति हरे रंग की भी होती है, जिसे ब्रोकली कहा जाता है। लेकिन अब आपको नारंगी तथा बैगनी रंग की गोभी भी देखने को मिलेगी। पोषक तत्वों से भरपूर ग्रीन ब्रोकली की जगह जल्द ही ऑरेंज और बैंगनी फूल गोभी ले लेगी। यह रंगीन गोभी दिखने में जितनी आकर्षक है, उससे कहीं ज्यादा पौष्टिक है। सागर के कृषि विज्ञान केंद्र में फूलगोभी की इस नई किस्म को प्रायोगिक तौर पर लगाया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र की पोषण वाटिका में नवंबर में लगाई इन गोभियों में अब फसल आ गई है। रंगीन सब्जी की होटल व रेस्टोरेंट में डिमांड भी है। सेहत के हिसाब से लोगों के साथ ही गोभी की यह

नई किस्म किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। जैविक विधि से तैयार होने वाली इस फसल का बाजार में आम गोभी की जगह चार गुना तक अधिक दाम मिलने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं।

गोभी 80 दिन में तैयार

गोभी की इन किस्मों कि यह फसल 80 दिनों में तैयार हो जाती है और इसमें तैयार एक गोभी 1-2 किलो तक होती है। इन रंगीन गोभियों में आम गोभी की तुलना में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है। इसके प्रयोग से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बुजुर्ग और गर्भवतियों के लिए सेवन बेहद फायदेमंद होता है। केंद्र की इस फसल को टमाटर के साथ लगाने पर कीट-व्याधि के प्रकोप का खतरा कम हो जाता है और श्रम और उर्वरक की भी बचत होगी।

सागर जिले में गोभी की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन ज्यादा उत्पादन होने पर किसान को वाजिब दाम नहीं मिल पाता। गोभी की यह रंगीन किस्म लगाने से यह लोगों को आकर्षित करेगी। इसके पोषक तत्वों की उपस्थिति इसे अच्छे दाम भी दिलाएगी।

डॉ. केएस यादव, निदेशक, कृषि विज्ञान केंद्र, सागर

मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा-

-सैटेलाईट से नरवाई जलाने की हो रही मॉनिटरिंग

खेतों में नरवाई जलाने पर गिरेगी सरकार की गाज

जागत गांव हमार, भोपाल।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में फसलों विशेषत: धान और गेंहू की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को खेतों में जलाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में जारी निर्देशों के उल्लंघन किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आग लगाने के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दंड का प्रावधान निर्धारित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक व्यवस्था बनाकर बेहतर पर्यावरण जन स्वास्थ्य एवं जीव-जन्तुओं की जीवन सुरक्षा प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/ किसान जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो 5 हजार और 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार रुपए प्रति घटना के मान से आर्थिक दंड भरना होगा।

कृषि विस्तार अधिकारी संभालेंगे कमान

दंड वसूलने के लिए संबंधित व्यक्ति /निकाय/कृषक जिनके द्वारा नरवाई जलाकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई है, को उप संचालक कृषि सूचना-पत्र जारी करेंगे। सूचना-पत्र को तामिल कराने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी की होगी। संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे और तामिल किए गए सूचना पत्रों की सूची अनुविभागीय कृषि अधिकारी उप संचालक कृषि को पेश करेंगे।

कृषि विस्तार अधिकारी, हल्का पटवारी और पंचायत सचिव के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। जरूरत पड़ने पर संबंधित थाने से पुलिस बल भी साथ में लिया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि नरवाई जलाने से किसानों को रोकने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है। आईसीएआर-कीव्स द्वारा देश में नरवाई में आग लगाने की मॉनिटरिंग सैटेलाईट के माध्यम से की जा रही है।

एदल सिंह कंषाना, कृषि मंत्री

एफपीओ को मजबूत बनाना किसानों की आत्मनिर्भरता की कुंजी

नई तकनीक और सहकारिता से होगा किसानों का उत्थान, कृषि क्रांति 2025 एफपीओ कॉन्क्लेव में दिए गए कृषि रत्न सम्मान

जागत गांव हमार, भोपाल।

सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि नई तकनीक और सहकारिता से किसानों का उत्थान होगा। खेत, खलियान और किसान सरकार की प्राथमिकता है। विकसित भारत की परिकल्पना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन तीनों के उन्नयन और उत्थान की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने से ही देश विकसित हो पाएगा, सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। मध्यप्रदेश ने कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इससे प्रोडक्शन में रिकॉर्ड दर्ज किया और 7 बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला। मंत्री नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कृषि क्रांति 2025 एफपीओ कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भी उपस्थित थे। मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कृषि को उन्नत बनाने हर क्षेत्र में काम किया है। किसानों को फसल का सही मूल्य मिल सके, समय पर उपार्जन सहित खाद, बीज, पानी मिल सके इसका ध्यान रखा गया है। अब किसान को व्यवसायी के रूप में परिवर्तन करना सरकार का मुख्य काम है और यह केवल सहकारिता के माध्यम से ही हो सकता है। किसानों को एफपीओ के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती से जोड़ना होगा, जिससे उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। एफपीओ को किसानों को जागरूक करना होगा। सरकार एफपीओ को हर तरह की सुविधा देने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष- 2025 में हर पंचायत में पैक्स के माध्यम से सहकार सभा होगी। इसमें भी एफपीओ जोड़कर किसान को सरकार से समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं।

खाद्य प्र-संस्करण से किसानों की आत्मनिर्भरता

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री कुशवाह ने कहा कि एफपीओ और खाद्य प्र-संस्करण को मजबूत बनाना किसानों की आत्मनिर्भरता की कुंजी है। उन्होंने फसल विविधीकरण और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही एक विशाल फूड प्रोसेसिंग सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें किसानों, उद्यमियों, क्रेताओं और विक्रेताओं को एक मंच पर लाया जाएगा।

मंत्री कुशवाह ने कहा कि किसान की आय दोगुना करने के लिये चल रहे कार्यों से फसलों का मूल्य अच्छा मिल सकेगा और उसका संवर्धन हो सकेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मप्र मसाला उद्योग में एक नम्बर पर है। सरकार अलग-अलग योजनाओं से किसानों की उत्थान की दिशा में काम कर रही है। उद्यानिकी विभाग के पोर्टल पर नये किसानों को रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

विकसित कृषि के लिये नई खेती से जुड़ना होगा, इसके लिये किसान उद्यानिकी से भी जुड़े। मंत्री कुशवाह ने कहा कि कई देश जैविक खेती में आगे बढ़ रहे हैं। जैविक खेती से पैदा होने वाली फसल से दुष्प्रभाव नहीं होता। इससे बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता और स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्र-संस्करण के क्षेत्र में कोई भी परियोजना व्यक्ति या संस्था लगाती है तो 35 प्रतिशत अनुदान सरकार दे रही है। साथ ही अनेक योजनाओं और कृषि उपकरण में भी सरकार अनुदान दे रही है। मंत्री कुशवाह ने कहा कि आधुनिक कृषि यंत्र खराबी पर मैकेनिक एवं उपकरण स्टोर, प्रबंधन आदि आवश्यक है। इस पर भी ध्यान देकर आगे बढ़ा जा सकता है।

कृषि क्रांतिः एफपीओ कॉन्क्लेव में अधिकारियों, विशेषज्ञों, निर्यातकों, क्रेताओं और तकनीकी प्रदाताओं ने एफपीओ के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य एफपीओ को खाद्य प्र-संस्करण और निर्यात योग्य उत्पाद तैयार करने में सक्षम बनाना था।

सहकार की भावना मजबूत होगी

मंत्री ने कहा कि एफपीओ कॉन्क्लेव से सहकार की भावना मजबूत होगी। सहकारिता मानव स्वभाव का मूलभूत आधार है। सहकारिता के बिना इस समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आज के समय में सहकारिता के माध्यम से नई-नई तकनीक से जोड़ना, फूड प्रोसेसिंग आदि पर काम करना, खेती में वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता हैं, जिससे अच्छे परिणाम आए इसमें सरकार सहायता देने को तैयार है। सरकार के साथ समाज जनता सहकारी संस्थाओं एफपीओ सब मिलकर काम करें, इस दिशा में कार्य करने के लिए सरकार प्रदेश के उन्नयन के लिए तत्पर है।

विशेषज्ञों के विचार एवं मार्गदर्शन

कृषिका नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक प्रतिभा तिवारी, डिक्की के अध्यक्ष डॉ. अनिल सिरवैया और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसायटी की अध्यक्ष डॉ. मोनिका जैन ने भी कॉन्क्लेव में विचार रखे। कॉन्क्लेव में सॉलिडरिडाड के जनरल मैनेजर सुरेश मोटवानी, एसबीआई के एजीएम शशांक कुमार, एमपी स्टार्ट-अप सेंटर के अरुणाभ दुबे, सी-मैप लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आलोक कृष्णा और उद्यानिकी विभाग के अपर संचालक श्री कमल सिंह किरार प्रमुख थे।

कृषि रत्न सम्मान एवं सहयोग

समारोह में 8 एफपीओ और 2 किसानों को कृषि रत्न सम्मान प्रदान किया गया। इनका सम्मान पत्र बांस से तैयार किया गया था। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 2 एफपीओ को 28.5 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई, जिसकी पहली किश्त सहकारिता मंत्री और एनएसडीसी की क्षेत्रीय निदेशक इंद्रजीत कौर ने प्रदान की। इस मौके पर लक्ष्य प्राप्ति के सूत्र पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

केंद्र ने एमजीएनआरईजीए कार्यस्थल पर बढ़ाई निगरानी

-सबसे अधिक 3.79 लाख जॉब कार्ड असम से हटाए गए

नरेगा से जुड़े 15 लाख फर्जी श्रमिकों के जॉब कार्ड हटाए

जागत गांव हमार, भोपाल।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) से जुड़े श्रमिकों के जॉब कार्ड का दुरुपयोग किए जाने की शिकायतों और सूचनाओं पर केंद्र सरकार ने 15 लाख से ज्यादा एक्टिव जॉब कार्ड को हटा दिया है। असम राज्य से सर्वाधिक 3 लाख से अधिक जॉब कार्ड हटाए गए हैं, जबकि, बिहार और ओडिशा से भी भारी संख्या में जॉब कार्ड को रद्द किया गया है। वहीं, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कार्यस्थल पर मौजूद श्रमिकों की दो बार फोटो जियो टैगिंग की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार वित्तवर्ष 2024-25 के दौरान 34 राज्यों में 15,12,864 सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड को हटाया गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्य सभा में एक जवाब में यह जानकारी दी। बताया गया कि महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की है। जॉब कार्डों का अपडेट करना, हटाना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाने वाला एक नियमित कार्य है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्तवर्ष 2024-25 में देशभर में 15,12,864 नरेगा जॉब कार्ड हटाए गए हैं। जबकि, इससे पहले 2023-24 में हटाए गए जॉब कार्ड की संख्या 34,84,691 थी और उससे पहले 2022-23 में 54,55,513 जॉब कार्ड सिस्टम से हटाए गए थे। जॉब कार्ड का हटाया जाना मुख्य रूप से नकली, डुप्लिकेट, गलत जॉब कार्ड, परिवार का ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाना, ग्राम पंचायत को शहरी के रूप में वर्गीकृत कर देने आदि कारणों से होता है।

असम से सर्वाधिक फर्जीवाड़ा

मौजूदा वित्तवर्ष 2024-25 में सर्वाधिक 3.79 लाख जॉब कार्ड असम से हटाए गए हैं। इसके बाद बिहार से 2.51 लाख जॉब कार्ड हटाए गए हैं। ओडिशा से 2.22 लाख और झारखंड के 1.51 लाख जॉब कार्ड हटाए गए हैं। हटाए गए जॉब कार्ड को ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं में सत्यापन के लिए चस्पा किया जाए। ताकि, श्रमिकों को अपील का अधिकार इस्तेमाल करने का मौका मिल सके।

सरकार ने निगरानी बढ़ाई

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों में नरेगा के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता के लिए निर्णय लिया है कि राज्य नरेगा कार्यस्थल पर एक दिन में कार्यकर्ता की जियो-टैग की गई दो टाइम मुहर लगी तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यदि कार्यस्थल नेटवर्क कवर्ड एरिया में नहीं है या किसी अन्य नेटवर्क समस्या के चलते उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकी है, तो उपस्थिति को ऑफलाइन मोड में दर्ज किया जा सकता है। डिवाइस के नेटवर्क कवर्ड एरिया में आने पर अपलोड किया जा सकता है।

नगदी फसलः अब चार गुना मुनाफे की उम्मीद

किसान ने शुरू की औषधीय फसल की खेती

जागत गांव हमार, सागर।

मध्यप्रदेश का बुंदेलखंड अंचल अब खेती में नवाचारों के लिए जाना जाने लगा है। यहां के किसान पारंपरिक खेती की जगह इसे लाभ का व्यवसाय बनाने के प्रयास कर रहे हैं। अब वे नगदी फसलों के उत्पादन में रुचि दिखा रहे हैं। सागर जिले की रहली और देवरी तहसीलों के युवा किसानों ने नवाचार करते हुए औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती शुरू की है। इन तहसीलों के किसान लगभग 200 एकड़ में अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं। रहली तहसील के ग्राम रजवांस के युवा किसान प्रशांत पटेल ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अश्वगंधा की खेती की जानकारी प्राप्त की और इसे अपनाया। पहले वर्ष 1 एकड़ में फसल लगाई, जिसमें अच्छा मुनाफा हुआ। अब उन्होंने 6 एकड़ में इसकी खेती शुरू कर दी है। प्रशांत को लाभ होता देख गांव के 20 से अधिक युवा किसानों ने भी अश्वगंधा की खेती शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि अन्य पारंपरिक फसलों की तुलना में तीन गुना अधिक मुनाफा हो रहा है। यह फसल कम लागत वाली, कम जोखिम भरी है। साथ ही इसमें पानी की भी विशेष आवश्यकता नहीं होती, जिससे किसान इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।

नीमच से लाए थे बीज- अश्वगंधा की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद किसानों ने यूट्यूब से इसके गुर सीखे और अपने परिचितों की मदद से नीमच और मंदसौर से बीज लाकर खेती शुरू कर दी। जिसका उन्हें खूब फायदा मिल रहा है।

कम लागत और अधिक लाभ

इस नवाचार पर जिले के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. आशीष त्रिपाठी बताते हैं कि अश्वगंधा जैसी औषधीय फसलों की कम लागत और अधिक लाभ के कारण किसान इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसकी खेता का रकबा लगातार बढ़ रहा है। अश्वगंधा एक औषधीय फसल है, जिससे विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। फिलहाल, किसानों को इसे बेचने के लिए नीमच या मंदसौर मंडी जाना पड़ता है। फसल की जड़ को निकालकर, उसकी ग्रेडिंग कर मंडी में बेचा जाता है। किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही स्थानीय स्तर पर ही इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी।

यह है लाभ का गणित

पारंपरिक फसलों की तुलना में अश्वगंधा की खेती किसानों को दोगुना-तिगुना मुनाफा देती है। कम लागत और कम जोखिम के कारण यह फायदेमंद साबित हो रही है। किसान बताते हैं कि अगर, एकड़ में गेहूं की फसल की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 22 क्विंटल पैदावार होती है। जिसे बेचकर उन्हें 55 हजार रुपए की आय होती है। वही, एक एकड़ में अश्वगंधा का औसतन 5 क्विंटल भी उत्पादन हो गया तो इसका भाव 25 से 30 हजार रुपए क्विंटल रहता है जिसको बेचकर उन्हें तिगुनी चौगुनी आय हो जाती है।

केंद्र ने महाराष्ट्र में 24, तेलंगाना में 15 दिन सोयाबीन खरीद अवधि बढ़ाई

एमएसपी पर सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, मसूर -उड़द खरीदेगी सरकार

जागत गांव हमार, भोपाल।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग-अलग राज्यों में मूंगफली और सोयाबीन की खरीद अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा, अगले चार वर्षों तक तुअर, मसूर और उड़द की 100 फीसदी खरीद को भी मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत 2025-26 तक इंटीग्रेटेड प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस योजना में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) और मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम आशा योजना का मकसद किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। शिवराज ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक 19.99 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं। महाराष्ट्र में 90 दिनों की सामान्य खरीद अवधि को 24 दिनों के लिए और तेलंगाना में 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है ताकि किसानों को एमएसपी पर फसल बेचने के लिए अधिक समय मिले।

» तुअर, मसूर और उड़द की 100 फीसी खरीदी 4 वर्षों तक जारी रहेगी

» भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से लिया गया निर्णय

मूंगफली की खरीद अवधि

सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में मूल्य समर्थन योजना के तहत मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अलावा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों के हित में गुजरात में मूंगफली की खरीद अवधि 90 दिनों की सामान्य खरीद अवधि से 6 दिन और कर्नाटक में 25 दिन बढ़ा दी है।

तुअर, उड़द-मसूर की 100 फीसदी खरीद

केंद्र ने दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100 फीसदी के बराबर पीएसएस के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है। सरकार ने बजट 2025 में यह भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से राज्य के उत्पादन के 100 फीसदी तक तुअर, उड़द और मसूर की खरीद अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी, जिससे दालों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत दालों में आत्मनिर्भर बनेगा।

चारा और आश्रय स्थलों पर राज्य सरकार का फोकस

10 से ज्यादा गायों का पालन पर किसानों को अनुदान

गायों के संरक्षण-विकास पर खर्च होंगे 478 करोड़

जागत गांव हमार, भोपाल।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते सप्ताह गायों के चारे पर प्रतिदिन खर्च को बढ़ाने के साथ ही नए गो संरक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि गायों के संरक्षण, आश्रय और विकास के लिए गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को 478 करोड़ प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार का फोकस मवेशियों के लिए चारा व्यवस्था, गायों के संवर्धन और आश्रय स्थलों के निर्माण पर है। राज्य सरकार गाय पालकों की भी आर्थिक मदद के लिए योजना चला रही है। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि राज्य में खेती गतिविधियों में तेजी लाने के साथ ही उपज खरीद और बिक्री के लिए मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश का विकास किया जा रहा है। राज्य में किसानों की उपज खरीद और भुगतान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाने के लिए 80 से ज्यादा मंडियों को पूरी तरह डिजिटल कर दिय गया है। राज्य की 41 बी क्लास मंडियों को 1 जनवरी 2025 से डिजिटल किया गया है।

कृषि अनुसंधान के लिए 756 करोड़ मिले

मप्र के कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि अंतर्गत अब तक 756.95 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं। इस राशि से 753.40 करोड़ रुपये विभिन्न संस्थाओं को अनुदान के रूप में दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसान सड़क निधि के तहत अब तक 7616.41 करोड़ रुपये में से प्रदेश की सड़कों के विकास के लिये 4107.81 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

10 गाय पालने पर अनुदान

राज्य सरकार पहले से छुड़ा गायों की देखरेख के लिए किसानों को सौंप रही है। इसके लिए गाय को पालने वाले किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है। राज्य सरकार के अनुसार जो किसान 10 से ज्यादा गायों का पालन करेंगे उन्हें अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे किसानों को गायों के दूध की खरीद पर बोनस राशि की व्यवस्था भी की गई है।

गौ संरक्षण के लिए 478 करोड़ मिले

राज्य के कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पशुपालन पर खास जोर दिया जा रहा है। इसके लिए गो संरक्षण योजना के तहत गायों का संरक्षण, गायों की उन्नत ब्रीड तैयार की जा रही हैं। कृषि मंत्री की ओर से कहा गया है कि गौ-संरक्षण तथा संवर्धन निधि में 479.30 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें से मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को 478.50 करोड़ रुपये समस्त जिलों की गौशालाओं को अनुदान स्वरूप प्रदान किये गये हैं।

सीएम बोले-पंचायत प्रतिनिधि जिम्मेदारी के साथ करें काम

सिहंस्थ-2028 की व्यवस्थाओं का विस्तार गावों तक होगा

जागत गांव हमार, भोपाल।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिहंस्थ-2028 का व्यवस्थित और सफल आयोजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिंहस्थ की व्यवस्थाओं का विस्तार उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तक होगा, अत: इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका रहेगी। सिंहस्थ के आयोजन में श्रद्धालुओं के आवागमन की दृष्टि से उज्जैन जनपद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इंडस्ट्रियल बेल्ट भी इसी क्षेत्र में विद्यमान है। यह सब बिंदु, क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

पंचायत प्रतिनिधि, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जनपद क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री, उज्जैन जनपद पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष भंवरबाई दुले सिंह चौधरी के उज्जैन जनपद में हुए पद ग्रहण समारोह को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों के कार्य को सराहा

मुख्यमंत्री ने पंचकोशी यात्रा की व्यवस्था के लिए एक करोड़ रुपए, क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़, उज्जैन जनपद में जिन पंचायतों के भवन नहीं हैं, वहां पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनपद पंचायत उज्जैन द्वारा ग्राम पंचायत भवनों के सौंदर्यीकरण के लिए किए गए कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारी कर्मचारियों के ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि विश्राम में सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने जनपद पंचायत उज्जैन द्वारा मैरिज गार्डन, गौशाला को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने, पारधी समुदाय की महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र संचालित करने और शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग तथा सोलर लाइट लगाने जैसे नवाचार के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की सराहना की।

किसान मजबूर, सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत

मप्र में तीन से पांच रुपए किलो टमाटर बेचने को मजबूर किसान

जागत गांव हमार, भोपाल।

पिछले कुछ महीनों तक टमाटर के दाम आसमान को छू रहे थे। यहां तक कि थोक मंडियों में भी कीमतें 50 रुपए प्रति किलोग्राम और इसके ऊपर चल रही थी, लेकिन अब बहुत-सी मंडियों में स्थिति एकदम उलट है और किसानों को 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान उपज बेचने को मजबूर हैं। खासकर मध्य प्रदेश में टमाटर की कीमतें बेहद कम देखने को मिल रही है। हालांकि, फुटकर मंडियों में उपभोक्ता को अभी भी एक किलो टमाटर खरीदने के लिए 30 रुपए या इससे अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं, सरकार की ओर से भी अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे टमाटर किसानों को राहत मिल सके। जानिए एमपी समेत अन्य राज्यों की विभिन्न मंडियों में टमाटर का क्या भाव चल रहा है।

मंडियों में टमाटर का भाव

मंडी	रुपए/ क्विंटल	रुपए/ क्विंटल	औसत कीमत /क्विंटल
बड़वानी	800	800	800
सारंगपुर	500	1000	700
सनावद	800	1000	900
सागर	300	500	400
श्योपुरकलां	500	600	550
धामनोद	600	800	700
टिमरनी	500	500	500

देश की अन्य मंडियों में टमाटर का भाव

मंडी	रु./क्विंटल)	रु./क्विंटल	औसत कीमत /क्विंटल
राजस्थान	1180	1200	1190
तमिलनाडु	2000	2400	2400
तमिलनाडु	2500	3000	3000
ओडिशा	2000	3000	2500
ओडिशा	2000	3000	2500
आंध्र प्रदेश	1400	1700	1600
असम	500	700	600
तमिलनाडु	2400	2400	2400
तमिलनाडु	2500	2800	2800
तमिलनाडु	1800	1800	1800

जलवायु संकटः अनचाही बारिश व तापमान बढ़ा रहा है डेंगू के मामले

एक नए अध्ययन में तापमान और बारिश को दुनिया भर में डेंगू के मामलों में वृद्धि के मुख्य कारणों के रूप में पहचाना गया है। साथ ही शोधकर्ताओं ने बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए नई रणनीतियों का भी सुझाव दिया है। मच्छरों से होने वाली बीमारी में डेंगू बुखार एक खतरनाक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, केवल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में 2023 में डेंगू के मामलों की संख्या 41 लाख से बढ़कर 2024 में 1.06 करोड़ से अधिक हो गई है। शोध के मुताबिक, दुनिया भर में यह संख्या अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। जबकि तापमान और बारिश जैसे जलवायु कारण इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं।

पिछले अध्ययनों ने परस्पर विरोधी निष्कर्षों को समेटने का काम किया है, कुछ सुझाव देते हैं कि बारिश डेंगू के फैलने को बढ़ाती है, जबकि अन्य कहते हैं कि यह इसे दबा देती है।

शोध में कहा गया है कि इंस्टीट्यूट फॉर बेसिक साइंस (आईबीएस) के शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि ये विसंगतियां पारंपरिक तरीकों की सीमाओं से उत्पन्न होती हैं जो खुले प्रभावों पर गौर करते हैं। इसे हल करने के लिए, शोधकर्ताओं ने जीओबी का उपयोग किया, जो अनुमान लगाने का एक नया उपकरण है जिसे आईबीएस की टीम ने 2023 में विकसित किया था।

यह विधि जलवायु के कारणों के प्रभावों को पकड़ती है, जिससे मौसम और डेंगू की घटनाओं के बीच संबंधों का अधिक गहराई से विश्लेषण कर पाना संभव हो पाता है।

अध्ययन में फिलीपींस के 16 क्षेत्रों पर गौर किया गया, जिन्हें उनकी विविध जलवायु परिस्थितियों के कारण चुना गया था, ताकि यह जांचा जा सके कि तापमान और बारिश मिलकर डेंगू के फैलने को किस तरह प्रभावित करते हैं।

तापमान और बारिश दोनों के प्रभावों से फिलीपींस में डेंगू फैलने के अलग-अलग पैटनर्ज सामने आए। बढ़ते तापमान लगातार सभी क्षेत्रों में डेंगू की घटनाओं में वृद्धि से जुड़े पाए गए। दूसरी ओर, बारिश ने इलाके के जगह के आधार पर विपरीत प्रभाव दिखाए। पूर्वी क्षेत्रों में बारिश ने डेंगू की घटनाओं को बढ़ा दिया, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में, बारिश ने इसे दबा दिया।

सबसे अहम कारण शुष्क मौसम की अवधि में भिन्नता थी, जिसे बारिश के विपरीत प्रभावों को समझाने के लिए जरूरी माना गया। शुष्क मौसम की अवधि में कम विविधता वाले क्षेत्रों में, बारिश ने स्थिर पानी को बाहर निकाल दिया, जिससे मच्छरों के प्रजनन स्थल कम हो गए और डेंगू संक्रमण कम हो गया।

दूसरी ओर, शुष्क मौसम की लंबी अवधि में भारी विविधता वाले क्षेत्रों में, बारिश ने नए प्रजनन स्थल बनाए और पानी के बाहर निकलने को कमजोर कर दिया, जिससे मच्छरों की आबादी और डेंगू के मामलों में वृद्धि हुई।

शुष्क मौसम की लंबी अवधि की भूमिका को पिछले शोध में काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है, लेकिन इस अध्ययन में यह एक निर्णायक कारण साबित हुआ। यह खोज बारिश और डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच जटिल संबंधों पर एक नया नजरिया प्रदान करती है।

शोध के मुताबिक, निष्कर्षों को परखने के लिए, शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण को प्यूर्टो रिको तक बढ़ाया, जो अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों वाला इलाका है। सैन जुआन, एडजुंटास और पोंस सहित नगर पालिकाओं के आंकड़ों ने समान पैटनर्ज प्रदर्शित किए, जो परिणामों की समानता को सामने लाता है।

शोध पत्र में शोधकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि शोध के निष्कर्ष इस बात के लिए अहम सबूत प्रदान करते हैं कि जलवायु कारक अलग-अलग वातावरण में डेंगू फैलने को कैसे प्रभावित करते हैं। यह समझने की दिशा में एक महत्वपूणर्ज कदम है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में मच्छर जनित बीमारियों को कैसे फैला सकता है।

शोध के निष्कर्षों में डेंगू पर लगाम लगाने की रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए तत्काल उपयोग किया जा सकता हैं। कम विविधता वाले क्षेत्रों के लिए, बरसात के मौसम के दौरान प्राकृतिक तरीके से पानी के बाहर निकलने के प्रयासों को कम कर सकते हैं, जिससे अन्य जरूरतें संसाधन मुक्त हो सकती हैं।

विशेष रूप से, छिटपुट बारिश द्वारा बनाई गई प्रजनन-अनुकूल स्थितियों का मुकाबला करने के लिए विविधता वाले क्षेत्रों में लगातार और साल भर लगाम लगाने के प्रयास जरूरी हैं।

इसके अलावा अध्ययन डेंगू के प्रकोप के लिए एक पूर्वानुमान के रूप में शुष्क मौसम की लंबी अवधि तक की निगरानी के महत्व को उजागर करता है। विशिष्ट क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न के लिए रणनीतियों को तैयार करके, सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां डेंगू के फैलने से निपटने के लिए संसाधनों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकती हैं।

यह अध्ययन यह समझने में अहम है कि जलवायु परिवर्तन न केवल डेंगू बुखार को फैलाने में मदद करता है, बल्कि मलेरिया, इन्फ्लूएंजा और जीका वायरस जैसी अन्य जलवायु संचालित बीमारियों पर भी असर डालता है।

साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र में शोधकताज के हवाले कहा गया है कि यह शोध संबंधों का पता लगाने के लिए पारंपरिक तरीकों की सीमाओं को पार करता है। यह एक उन्नत अनुमान एल्गोरिथ्म के माध्यम से जलवायु के बदलाव और संक्रामक रोगों के बीच जटिल आंतरिक क्रियाओं को स्पष्ट करता है। इस नजरिए को जलवायु से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के विश्लेषण पर भी लागू किया जा सकता है। जबकि अध्ययन मजबूत नजरिया प्रदान करता है, शोधकताज कुछ सीमाओं को स्वीकार करते हैं, जिसमें मच्छरों की आबादी के आंकड़ों की कमी और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और लोगों की गतिविधि जैसे सामाजिक आथिज्क कारण शामिल हैं। साप्ताहिक डेंगू की घटनाओं और मच्छरों की गतिशीलता जैसे अधिक विस्तृत आंकड़ों तक पहुंच के साथ भविष्य के अध्ययन इन निष्कर्षों को और अधिक सुधार सकते हैं।

भारत के कृषि बाजार पर ट्रंप की नजर, एग्री सेक्टर की बढ़ेंगी मुश्किलें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'जैसा को तैसा' टैक्स को लागू करने के प्रस्ताव से दुनियाभर में हलचल मची हुई है। इससे कृषि समेत कई सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। जबकि, उत्पादों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। कृषि एक्सपर्ट का मानना है कि अगर अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाता है, तो अमेरिकी बाजार में इन उत्पादों की कीमतें भी बढ़ेंगी, जिससे उनकी मांग में कमी आ सकती है। इससे भारतीय कृषि निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। खासकर उन उत्पादों के लिए जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। DGCIS के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2023-24 में भारत ने अमेरिका से 11,893 करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का आयात किया, जबकि इस दौरान भारत ने 12,435 करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का अमेरिका को निर्यात किया है।

भारत ये कृषि उत्पाद अमेरिका से खरीदता है: अमेरिका के प्रस्तावित पारस्परिक शुल्क भारतीय कृषि क्षेत्र पर महत्वपूणर्ज प्रभाव डाल सकता है. क्योंकि, इससे कीमतें प्रभावित होंगी. बता दें कि उन्होंने परस्पर शुल्क एक देश दूसरे देश की ओर से लगाए गए शुल्कों के प्रत्युत्तर में लागू करता है. भारत अमेरिका से मसूर, मटर दाल समेत कपास, बादाम, अखरोट, मीट-मछली, सीफूड, कॉफी, डेयरी उत्पाद और ताजे फलों को आयात करता है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार साल 2023-24 में भारत ने अमेरिका से 11,893 करोड़ रुपये की कृषि उत्पादों का आयात किया, जिसमें सबसे ज्यादा 8664 करोड़ का खचज ताजे फ्लों पर किया गया था।

भारत से 13 हजार करोड़ के कृषि उत्पाद खरीदता है: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े बताते हैं कि भारत अमेरिका को सालाना 12,435 करोड़ रुपये के खाद्यान्न, फल-सब्जियों का निर्यात करता है। इसमें मीट, डेयरी और दलहन उत्पाद भी शामिल हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2023-24 में भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले कृषि उत्पाद में चावल शामिल है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 2,527 करोड़ रुपये का 2.34 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। जबकि, 373 करोड़ रुपये का 53,630 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल निर्यात किया है। निर्यात किए गए अन्य कृषि उत्पादों में 1,489 करोड़ के डेयरी प्रोडक्ट, 1,129 करोड़ रुपये के प्रॉसेस फ्रूट और जूस, 758 करोड़ की प्रॉसेस सब्जियां, 478 करोड़ रुपये की दालें, 434 करोड़ रुपये के ताजा फल समेत कई उत्पाद शामिल हैं। DGCIS के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत ने अमेरिका को 12,435 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद निर्यात किए।

निर्यातकों और किसानों के लिए चुनौती बनेंगे शुल्क: कृषि एक्सपर्ट ने बताया कि अमेरिका से आयात होने वाले कृषि उत्पादों पर भारत की ओर से लगाए गए टैरिफमें संभावित बदलाव से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जो भारतीय किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि पारस्परिक शुल्कों का भारतीय उद्योग के बड़े हिस्से पर सीमित प्रभाव होगा। कुछ विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका के परस्पर टैरिफसे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो सकता है, लेकिन यह प्रभाव व्यापक नहीं होगा। पारस्परिक शुल्कों का सटीक अर विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करेगा जैसे कि टैरिफ की दरें, प्रभावित उत्पादों की सूची और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की स्थिति।

भारतीय कृषि निर्यात पर प्रभाव और घरेलू बाजार में अवसर: कृषि तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ अक्षय खोब्रागड़े ने कहा कि अमेरिकी परस्पर शुल्कों के लागू होने की संभावना पर कहा कि इस तरह के शुल्कों से भारतीय कृषि निर्यातों पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही यह कुछ नई संभावनाओं के दरवाजे भी खोल सकता है। यदि अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों पर अधिक शुल्क लागू करता है, तो इससे भारतीय उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा घट हो सकती है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भारतीय कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ने से इन उत्पादों की मांग में कमी हो सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को निर्यात वॉल्यूम में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जो सीधे तौर पर उनकी आय को प्रभावित करेगा। इसके अलावा खोब्रागड़े का मानना है कि शुल्कों के चलते भारत के घरेलू कृषि क्षेत्र को एक नया अवसर मिल सकता है। यदि अमेरिका से निर्यात में कमी आती है तो भारतीय उपभोक्ताओं का रुझान स्थानीय उत्पादों की ओर हो सकता है, जिससे भारतीय किसानों को अपने उत्पादों के लिए एक नया बाजार मिल सकता है।

विकसित भारत के लिए कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और यह कहना सर्वथा उचित है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पीएम मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज आर्थिक महाशक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा रहा है। भारतीय कृषि ने बीते एक दशक में, मोदी सरकार के दो कार्यकाल के दौरान प्रगति के नए आयामों को छुआ है और अब लगातार तीसरे टर्म में भी समग्र कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रति हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता इसी से परिलक्षित हो रही है कि पिछले आठ महीनों के दौरान लगभग सभी कैबिनेट बैठकों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भलाई के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। कृषि को सर्वोपरि रखने की बात का अंदाजा बहुत सहजता से इससे भी लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के प्रारंभ में, विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि का उल्लेख किया गया है। बीते एक दशक में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने, गरीबी दूर करने, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने व कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य किया, जिसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने हैं। सरकार कृषि आधारित उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रही है। इसमें फसल विविधीकरण से लेकर पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन, खाद्य प्रसंस्करण, मछली पालन, वर्मीकंपोस्ट और कृषि मशीनरी निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इनके माध्यम से किसान अपनी आय बढ़ाते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से किसानों को फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आ रही है, वहीं प्रसंस्करण क्षमता और निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर किसानों को इन नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया है। फसल विविधीकरण के बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोषक अनाज, दलहन, तिलहन सहित अन्य फसलों की एमएसपी में लगातार वृद्धि क गई है, वहीं कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों व स्मार्ट उपकरणों क उपयोग किया जा रहा है, जिससे किसान न केवल अधिक उपज प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि बाजार में बेहतर मूल्य पा सकेंगे।

शासन की ओर से बजट बढ़ाने के बाद भी सड़कों पर डंडे खा रहीं गौमाताएं

दिखावा बनकर रह गई गांव-गांव शासन की ओर से खुली गौशालाएं

गायों की बेकद्री पर हाईकोर्ट सख्त श्योपुर सहित नौ कलेक्टरों को नोटिस

जागत गांव हमार, श्योपुर।

हिंदू समाज में गाय को माता का दर्जा दिया जाकर उसकी पूजा की जाती है। वहीं सरकार की ओर से गौवंश के संरक्षण के लिए बजट भी बढा दिया गया है,लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी श्योपुर जिले में काफी संख्या में गौमाताएं शहर सहित जिले की सड़कों पर निराश्रित घूमकर डंडे खाने को मजबूर हो रही है। आवारा घूम रही इन गायों को किसान गांवों की ओर हांक रहे हैं, तो गांव के लोग इन गायो को डंडा लेकर शहर की ओर भगा रहे है। गांव गांव शासन की ओर से खोली गई गौशालाए भी दिखावा बनकर रह गई है। गौमाता की इस तरह हो रही बेकद्री पर न तो गौ सेवा का दंभ भरने वाले गौसेवकों की नींद टूटी और न ही सरकार की आंखें खुल पाई है। मगर ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस संबंध में सख्ती दिखाते हुए श्योपुर कलेक्टर को इस मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस श्योपुर कलेक्टर सहित ग्वालियर चंबल संभाग के नौ जिलों के कलेक्टर को दिया गया है और उनसे चार सप्ताह के भीतर जबाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

ग्वालियर हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका हरिओम झा की ओर से दायर की गई है। बताया गया है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को गौशाला में रखने के लिए राज्य व केंद्र शासन से अनुदान मिलता है, लेकिन जिलों में बनी गोशालाएं खाली पड़ी हैं और उनके नाम पर आने वाले पैसे को निकाला जा रहा है। यदि गौशालाओं की नियमित निगरानी की जाए, तो गाय गौशाला में शिट हो सकती हैं। राज्य शासन व जिले के कलेक्टरों को गायों को गौशाला में शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया जाए।

14 सरकारी और 7 अशासकीय गौशालाएं संचालित है जिले में

वैसे तो श्योपुर जिले में तीन दर्जन से ज्यादा गौशालाएं शासन की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत की गई है। लेकिन इनमें से अभी सिर्फ 14 सरकारी गौशालाएं ही ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित बताई जा रही हैं। जिनमें से प्रेमसर में बनी गौशाला में एक भी गौवंश नहीं है। इसके अलावा सात अशासकीय गौशालाए भी श्योपुर जिले में संचालित बनी हुई है। इनमें श्री गोपाल गौशाला श्योपुर, आशाराम गौशाला ढेंगदा और रानीपुरा, हांसिलपुर ढोढर, गसवानी, घमलोकी और श्यामपुर में अशासकीय गौशालाएं संचालित हो रही है। ऐसे में सवाल खडा हो रहा है कि 14 सरकारी और 7 अशासकीय गौशाला संचालित होने के बाद भी काफी संख्या में गौवंश सड़कों पर क्यों घूम रहा है।

हादसों का कारण भी बन रहा निराश्रित गौवंश

शहर सहित जिलेभर की सड़कों पर आवारा घूम रही गाए न सिर्फ बेक्रदी का शिकार हो रही है,बल्कि सड़क हादसों का कारण भी बन रही है। दरअसल शहरों पर आवारा घूम रहे गौवंश से टकराकर आए दिन सडक हादसे भी घटित हो रहे हैं। जिनमें लोगो की जान तक भी जा रही है। सबसे अधिक सड़क हादसे रात्रि के दौरान बाइको के टकराने के कारण घटित हो रहे हैं। इसके अलावा शहर की सडकों पर घूम रहा आवारा गौवंश बाजार में खरीदारी के लिए आ रहे लोगों को सींगे मारकर घायल भी कर रहा है। शहर सहित जिले में इस तरह की घटनाएं भी अब तक कई हो चुकी हैं।

किसान भी बने परेशान,क्योंकि फसले भी उजाड़ रहा निराश्रित गौवंश

आवारा घूम रहे निराश्रित गौवंश के कारण न सिर्फ शहर श्योपुर के लोग ही परेशान नहीं बने है,बल्कि गांवों में किसान भी इन आवारा मवेशियों के कारण बुरी तरह परेशान नजर आ रहे है। क्योंकि यह आवारा गौवंश खेतो में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे है। ऐसे में किसान भी डंडे लेकर इन आवारा गौवंश को इस गांव से उस गांव भगा रहे हैं।

श्योपुर कलेक्टर के साथ इन्हें भी दिया गया नोटिस

हाईकोर्ट द्वारा श्योपुर कलेक्टर के साथही ग्वालियर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, भिंड, विदिशा, गुना, अशोकनगर के कलेक्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनके अलावा नगर निगम आयुक्त ग्वालियर, केंद्र शासन, पशु चिकित्सा विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, संयुक्त संचालक पशुपालन विभाग को नोटिस जारी किए गए हैं।

श्योपुर जिले के सामान्य वन मंडल और कूनो वन मंडल में भी होगी गिद्ध गणना,तैयारियां पूरी

आज से पूरे मप्र में एक साथ आरंभ होगी गिद्धों की गणना, तीन दिन चलेगा काम

जागत गांव हमार, श्योपुर।

गिद्धों की गणना 17 फरवरी से आरंभ होगी। जो तीन दिनों तक चलेगी। खास बात यह है कि गिद्धों की यह गणना श्योपुर जिले के जंगल में ही नही अपितु मप्र के सभी जिलो के जंगल में एक साथ होगी। इस गिद्ध गणना की तैयारियां श्योपुर जिले में सामान्य वन मंडल और कूनो वन मंडल की ओर से पूरी कर ली गई है। दोनो वन मंडल का अमला सुबह के समय एक घंटे अपने अपने क्षेत्र में गिद्धों की गणना करेगा।

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गिद्धों की गणना हर साल की जाती है। इसी क्रम में इस साल गिद्धों की गणना का काम 17 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 18 और 19 फरवरी तक चलेगा। पूरे प्रदेश के साथ यहां श्योपुर जिले के सामान्य वन मंडल और कूनो वन मंडल के जंगल में भी गिद्धों की गणना की जाएगी। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली इस गणना में विभागीय टीमें शामिल रहेगी। वन विभाग की अलग-अलग टीमें तीनों दिनों तक निर्धारित समय में पूरे जिले के जंगल में घूमकर गिद्धों की गणना करेगी। बता दें कि वन विभाग को पिछली गणना के मुकाबले गिद्धों की तादाद में इस बार बढोत्तरी होने की उम्मीद है।

इन स्थानों पर होगी तलाश

वन क्षेत्र में गिद्ध अधिकांशत: ऊंची चट्टानों में अपने घोंसले बनाते हैं। इसलिए गणनाकर्मियों की नजरें सबसे ऊंची खड़ी चट्टानों पर रहेगी। साथ ही नदी व झीलों के किनारे, जलाशयों के आसपास भी गिद्धों की सर्चिंग होगी। ऐसे स्थानों पर गिद्ध सुबह शिकार की तलाश में निकलते हैं। बताया गया है कि यह गणना तीन दिनों तक सुबह 7 बजे से 8 बजे तक चलेगी। लेकिन जिन स्थानों पर ऊची चट्टाने है,वहां गणना सुबह 9 बजे तक की जा सकेगी।

वनकर्मियों को दिया जा चुका प्रशिक्षण

वन विभाग के द्वारा गिद्धों की गणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। डीएफओ करण सिंह ने बताया कि गिद्धों की गणना किए जाने के संबंध में मैदानी अमले को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह प्रशिक्षण पहले वृत स्तर पर और फिर जिला स्तर पर आयोजित किया गया है। जिसमें वनकर्मियों को गिद्धों की गणना किस तरह करनी है,इस बारे में विस्तार से बताया गया।

- गिद्धों की गणना 17 फरवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू होगी। जिले के सामान्य वन मंडल और कूनो वन मंडल के जंगल में 19 फरवरी तक चलने वाली गिद्धों की गणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली है।

करण सिंह, डीएफओ,
सामान्य वन मंडल श्योपुर

18 फरवरी तक करें आवेदन, 19 फरवरी 2025 दिन लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा

50 प्रतिशत तक सब्सिडी पर किसानों कृषि यंत्र देगी सरकार

जागत गांव हमार, भोपाल।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किसान इन यंत्रों को सब्सिडी पर प्राप्त करने के लिए 18 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद 19 फरवरी 2025 दिन लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन करना होगा। जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान- कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जो इस प्रकार है-

पॉवर वीडर, पॉवर टिलर (8 एचपी से अधिक)
पॉवर हैरो,
श्रेडर/ मल्चर,
स्ट्रॉ रीपर,
रीपर (स्व-चलित/ ट्रैक्टर चलित)।

कितना अनुदान मिलेगा- प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें किसानों को पॉवर वीडर के लिए 3100/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), पॉवर टिलर के लिए 5000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), पॉवर हैरो के लिए 3500/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), श्रेडर/मल्चर के लिए 5500/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), स्ट्रॉ रीपर के लिए 10,000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), रीपर के लिए 3300/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा। योजना के तहत किसानों का चयन नहीं होने पर डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि (डीडी) के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। किसान यह डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) ऊपर दी गई कृषि यंत्री की सूची के नाम से बनवा सकते हैं जो अलग-अलग जिले के लिए अलग-अलग है।

आवेदन के लिए दस्तावेज

ऊपर दिये गये सभी कृषि यंत्रों के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है, जिनका इस्तेमाल आवेदन के समय एवं कृषि यंत्र लेने के बाद उसके सत्यापन के समय होगा। जो इस प्रकार है:- आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी एवं अन्य आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी), बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), खसरा/खतौनी, बी1 की नकल, ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड।

यहां आवेदन कहाँ करें

मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऐसे में जो किसान ऊपर दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं वे किसान जिन्होंने ने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा और इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कायाज़्लय में संपर्क करें।

कृषि विज्ञान मेला सह टमाटर प्रसंस्करण की तैयारी बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश

जागत गांव हमार, झाबुआ।

जिले में 17 फरवरी को कृषि विज्ञान मेला सह टमाटर प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, बायर-सेलर कार्यशाला एवं युवा रोजगार सृजन परिसंवाद कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न विभागों को सौंपे गये दायित्वों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र. शासन निर्मला भूरिया के मुख्य आतिथ्य तथा सांसद-लोकसभा क्षेत्र रतलाम अनिता नागर सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों को सौंपे गये दायित्वों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया। जिसमें कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जिला झाबुआ को कार्यक्रम स्थल पर गुणवत्तायुक्त पेयजल व्यवस्था मय समस्त आवश्यक सामग्री, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला झाबुआ को कार्यक्रम आयोजन के पूर्व, आयोजन के दौरान तथा आयोजन उपरान्त परिसर, भवन, साफ-सफाई, चलित शौचालय-2, डस्टबिन, फायर ब्रिगेड, संभागीय यंत्री म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि. जिला झाबुआ को निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा विद्युत संबंधी सुरक्षा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस झाबुआ को यातायात एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था, खाद्य एवं औषधि अधिकारी जिला झाबुआ प्रशासन को कार्यक्रम स्थल पर वितरित किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए निर्देशित किया।

उक्त कार्यक्रम में जिले के कृषक समुदाय की आजीविका उन्नयन, टमाटर प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, बायर-सेलर कार्यशाला एवं युवा रोजगार सृजन परिसंवाद कार्यक्रम, नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों, आदानों उत्पादों तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न आयामों से परिचित कराने एवं शासन की कृषक/जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैठक में उप संचालक कृषि विभाग एन एस रावत, सहायक संचालक उद्यानिकी नीरज साँवलिया एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय पशु चिकित्सा शिविर में पशुपालकों दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

इंदौर। पशु कल्याण जागरूकता माह के अंतर्गत गत दिनों इंदौर जिले के ग्राम पंचायत अकवी विकासखंड महू में जिला स्तरीय नि:शुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि स्थाई समिति इंदौर के अध्यक्ष दिनेश चौहान, जनपद पंचायत अध्यक्ष महू सरदार सिंह मालवीय, उपाध्यक्ष बीरबल सिंह डाबर आदि उपस्थित थे।

शिविर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय महू के डीन डॉ. बी. पी. शुक्ला, डॉ. पवन माहेश्वरी, डॉ. अशोक पाटिल, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं इंदौर डॉ. शशांक जुमड़े, प्रभारी पशु चिकित्सालय डॉ. राकेश सिसोदिया ने उपस्थित पशुपालकों की शंकाओं का समाधान किया एवं उन्हें पशुपालन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

शिविर में 168 पशुओं का उपचार किया गया। शिविर में 276 बकरियों एवं 5 अन्य पशुओं का भी उपचार किया गया। शिविर में 305 पशुओं का टीकाकरण भी किया गया। मंच का संचालन डॉ. सी. एस. डाबर ने किया तथा शिविर में उपस्थित सभी का आभार डॉ. विवेक शर्मा ने व्यक्त किया।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत कार्यशाला आयोजित

जागत गांव हमार, धार।

उप संचालक उद्यान मोहनसिंह मुझाल्दा ने बताया कि जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अन्तर्गत आजीविका भवन माण्डव रोड़ में सेमीनार, कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें योजनान्तर्गत विभागीय योजनाओं के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विषय विशेषज्ञ सिद्धार्थ राठौर द्वारा पीएमएफएमई योजना में आवेदन, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के स्थापना हेतु आवश्यक मशीनों के संबंध में विस्तृत

जानकारी दी गई। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय धार के मुख्य प्रबंधक बलराम कुमार गुजराल द्वारा पीएमएफएमई योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु ऋण स्वीकृति के संबंध में विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया। साथ ही नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक सागरिका चाफेकर द्वारा नाबार्ड से संबंधित योजनाओं के संबंध में, कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एस.एस. चौहान द्वारा मृदा प्रबंधन एवं जैविक खेती के संबंध में, डॉ. डी. एस. मंडलोई उद्यानिकी वैज्ञानिक द्वारा जिले की प्रमुख फसलों के नवीन तकनिकी से उत्पादन एवं प्रसंस्करण के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। पीएमएफएमई योजनान्तर्गत दलिया मील इकाई की स्थापना करने वाले उद्यमी सचिन जायसवाल ने स्थापित इकाई की सफलता के संबंध में अपना अनुभव साझा किया । बताया गया कि वर्ष 2024-25 में पीएमएफएमई योजनान्तर्गत व्यक्तिगत एवं समूह इकाइयों के ऋण स्वीकृति पत्र वितरण किये गये। इस अवसर पर विकासखंड अधिकारी एवं जिले के समस्त विकासखंड के कृषक व पीएमएफएमई योजना के लाभार्थी उपस्थित रहे।

अश्वगंधा की औषधीय खेती से गंजबासौदा का किसान हुआ मालामाल

जन अभियान परिषद की सलाह पर शुरू की खेती

एक बीघा में लगाई अश्वगंधा, तीन से चार क्विंटल उत्पादन, एक लाख से ज्यादा के लाभ का अनुमान

जागत गांव हमार, गंजबासौदा।

धीरे धीरे किसान परंपरागत फसलों की खेती छोड़कर नगदी फसलों की खेती के तरफ रुख कर रहे हैं। नगदी फसलें कम समय में अच्छा मुनाफा दे रहीं हैं। ऐसी ही एक औषधीय फसल है अश्वगंधा, जो कम समय और कम लागत में ज्यादा फायद देती है। मप्र कई जिलों में किसान औषधीय खेती कर रहे हैं। विदिशा जिले के गंजबासौदा में ग्राम सुनारी के रहने वाले किसान राजेंद्र सिंह रघुवंशी ने परंपरागत खेती के साथ अश्वगंधा लगाई है। शुरुआत एक बीघा से की। उम्मीद है कि इसमें तीन से चार क्विंटल उत्पादन होगा। इससे करीब एक लाख रुपए से ज्यादा का लाभ होने का अनुमान है।

50 साल के राजेंद्र सिंह ने बताया कि, वर्तमान में हमारे पास 35 बीघा जमीन है। इस पर पारंपरिक फसलें जैसे गेहूं, चना, मसूर, तेवड़ा और धनिया उगा रहे हैं। खर्च काटकर सालाना करीब 8 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। छोटा भाई रामबाबू रघुवंशी भी परिवार के साथ सहयोग करता है। हमारा संयुक्त परिवार है। करीब एक साल पहले की बात है। जन अभियान परिषद के लोग गांव आए थे। उन्होंने अश्वगंधा की खेती के बारे में बताया। मुझे बात जम गई। इसके बाद कृषि विभाग से भी जानकारी ली। अश्वगंधा की मंडी और भाव का भी पता किया। ऑनलाइन वीडियो देखकर इसकी हर जानकारी हासिल की। करीब छह महीने की रिसर्च के बाद नवंबर 2024 में अश्वगंधा की फसल लगाई।

10 बीघा में अश्वगंधा की खेती करने की योजना

एक बीघा खेत से औसतन तीन से चार क्विंटल उत्पादन होता है। इसे बेचने के लिए मुख्य मंडी नीमच-मंदसौर है। वर्तमान में अश्वगंधा का बाजार भाव 35 से 40 हजार रुपए प्रति क्विंटल है। इस हिसाब से करीब डेढ़ लाख रुपए की फसल बिक जाएगी। करीब एक लाख रुपए से ज्यादा का फायदा होने की उम्मीद है। अगले साल 10 बीघा जमीन में अश्वगंधा लगाएंगे। करीब एक लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, जो पारंपरिक खेती में मुनाफे का दोगुना से ज्यादा है।

5 महीने की खेती, नवंबर में बुवाई

राजेंद्र कहते हैं, अश्वगंधा की खेती महज 5 महीने में तैयार हो जाती है। नवंबर का महीना इसकी बुवाई के लिए उपयुक्त है। मार्च-अप्रैल तक फसल तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसे काट लिया जाएगा। खास बात है कि एक बीघा में 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत एक हजार रुपए किलोग्राम रही। खेत की तैयारी में करीब एक हजार रुपए का अतिरिक्त खर्च आया। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल किया। इससे लागत और भी कम हो जाती है। इसमें सबसे अहम नियमित सिंचाई होती है। हर 15 दिन में एक बार यानी महीने में दो बार पानी देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर नुकसान भी हो सकता है।

ऐसे तैयार करें मिट्टी

किसान राजेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि इसकी खेती के लिए पहले मिट्टी की हकाई (मिट्टी को खोदना) करना पड़ती है। खेत में मिट्टी को 2-3 फीट तक खुदाई करनी होती है। इससे मिट्टी हवा और पानी अच्छे से सोख लेती है। इसके बाद मिट्टी को समतल करने से अश्वगंधा के पौधों को समान रूप से विकसित होने में मदद मिलती है। जैविक उर्वरकों जैसे गोबर की खाद और कम्पोस्ट का इस्तेमाल जरूरी है।

सही समय पर करें गर्मी की सब्जियों की

सही समय पर करें गर्मी की सब्जियों की बुआई, पाएं अच्छा मुनाफा

जागत गांव हमार, भोपाल।

गर्मी के सीजन में किसान सब्जियों की खेती करके अतिरिक्त आमदनी कर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ऐसे में जो किसान इस सीजन में सब्जियां लगाना चाहते हैं वे किसान अभी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों की पौध की तैयारी व बुवाई का यह उपयुक्त समय चल रहा है। बुवाई 15 फरवरी से 15 मार्च तक कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन सब्जियों लौकी, कद्दू, करेला, तोरई, खीरा, टिण्डा, भिंडी, तरबूज और खरबूज की बुवाई का यह उपयुक्त समय है।

किसान इस तरह करें सब्जियों की बुआई का काम- कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बेल वाली सब्जियों के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य हो उपयुक्त होती है। किसान मिट्टी की जांच रिपोर्ट के आधार पर गोबर की खाद या कम्पोस्ट अथवा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें। बुवाई के लिए नालियां या जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार कर लें। खेत में नालियां लगभग 40-50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30-40 सेंटीमीटर गहरी बनाएं। दो कतारों में 2 से 4 मीटर की दूरी रखें।

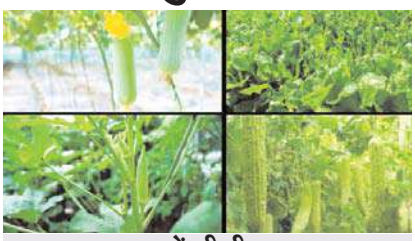

फसलों की बीज दर

खीरा के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, लौकी के लिए 4 से 5 किलोग्राम, करेला के लिए 5 से 6 किलोग्राम, तोरई के लिए 4.5 से 5 किलोग्राम, कद्दू के लिए 3 से 4 किलोग्राम, टिण्डा के लिए 5 से 6 किलोग्राम, तरबूज के लिए 4 से 4.5 किलोग्राम और खरबूज की बीज दर 2.5 किलोग्राम रखें। रोपाई से पूर्व सब्जियों के बीजों को फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम + मैन्कोजेब 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें। ज्यादातर बेल वाली सब्जियों में खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फॉस्फोरस 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें।

ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती

जो किसान गर्मी के सीजन में भिंडी लगाना चाहते वे फरवरी से मार्च के दौरान इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भिंडी की खेती के लिए उन्नत किस्में जैसे परभनी क्रांति, अर्का अभय, वीआरओ-5, वीआरओ-6, अकाउ अनामिका आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। पीला मोजेक रोग से बचाव के लिए बीज को बुवाई से पूर्व थायोमिथाक्जाम 30 एफएस मात्रा 10 मिली लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 48 एफएस मात्रा 1.25 मिली लीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। बुवाई के लिए बीज दर 20 से 22 किग्रा रखें एवं कतार से कतार की दूरी 25-30 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर एवं बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक न रखें। खेत में भिण्डी की बुवाई से पूर्व 2 से 2.5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिलाएं एवं रसायनिक उर्वरक में नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, स्फुर 30 किलोग्राम एवं पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें।

गर्मियों में बेहाल हो जाते हैं दुधारू पशु, अभी से शुरू कर दें ये तैयारी

जागत गांव हमार, भोपाल।

अधिक गर्मी इंसानों को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी परेशान करती है। खासकर दुधारू पशु अधिक परेशान होते हैं क्योंकि उनका मेटाबोलिक सिस्टम अधिक तेजी से काम करता है। इस बार फरवरी का महीना ही बढ़ते तापमान का संकेत दे रहा है। ठंड का कोई अता-पता नहीं और तापमान हर दिन बढ़ रहा है। हवाएं भी तेज चल रही हैं। इसे देखते हुए इस बार प्रचंड गर्मी का संकेत मिल रहा है। इसे देखते हुए पशुपालन करने वाले लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। खासकर जो किसान दूध के बिजनेस के लिए पशुपालन करते हैं।

गर्मी को देखते हुए किसानों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे, जिन पशुओं का मेटाबोलिक रेट अधिक होता है जिसमें ज्यादा दूध देने वाले पशु आते हैं, उन पशुओं को गर्मी से बचाना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा, जिन पशुओं को कम पसीना आता है जैसे सूअर और कुत्ते, उन्हें भी गर्मी से बचाना जरूरी होता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए किसानों को सावधान रहना चाहिए। पशुओं में कुछ संकेत दिख जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि वे गर्मी से परेशान हैं।

क्या कहते हैं संकेत

शारीरिक लक्षण: लेटना, सूखी नाक, कमजोरी, मांसपेशियों में कंपन, लार आना, गिरना, पेट में सूजन

सामान्य व्यवहार और एक्टिविटी: हरकत में कमी, पोश्चर में बदलाव, ज्यादा पीना, भूख न लगना

श्वसन और सांस लेने में बदलाव: हांफ्ना, जीभ बाहर निकालकर तेजी से हांफ्ना, मुर्गी के मामले में खुली चोंच से हांफना

तापमान से परेशानी के संकेत: लगातार छाया की तलाश करना, पानी के तीत पर ज्यादा समय बिताना, मुर्गी के मामले में पंख बाहर निकालना

दूध उत्पादन: दूध उत्पादन में कमी आना

किसान ये करें उपाय

सनबर्न: इससे सूअर और भेड़ों को अधिक परेशानी होती है। सनबर्न होने पर चमड़े पर लाल धब्बा बनता है, सूजन आती है, फफोले हो जाते हैं और बुखार आ जाता है। इसके लिए उपाय में पशु को पानी से नहलाएं, फफोलों पर ड्रेसिंग रखने की सलाह दी जाती है।

हीट क्रैम्प्स: आमतौर पर पैर और पेट की मांसपेशियों में ऐंठन के साथ पसीना आना। ऐसी स्थिति में पशु को ठंडी या छायादार जगह पर ले जाएं और ऐंठन वाले हिस्से की मालिश करें।

हीट थकावट/तनाव: बहुत ज्यादा पसीना आना, कमज़ोरी, त्वचा ठंडी और पीली, हांफना, सूखी नाक, सांस लेने में तेज़ी, सामान्य तापमान संभव। ऐसी स्थिति दिखे तो पशु को कूलर/पंखे के नीचे ठंडे शेड में रखें, जहां पीने का पानी उपलब्ध हो। पशुओं को एक साथ रखने की दर कम करें।

हीट स्ट्रोक: गंभीर और/या लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने के कारण पशुओं में यह समस्या हो सकती है। स्तनपान कराने वाले पशुओं में ज्यादा जोखिम होता है। इसके लक्षणों में गर्म, सूखी त्वचा और तेज़, मजबूत नाड़ी के साथ शरीर का उच्च तापमान शामिल है। इसके बचाव में शरीर के तापमान को कम करने के लिए पशु को ठंडे वातावरण में ले जाएं और ठंडे पानी से नहलाएं या स्पंज से पोंछें। जल्द से जल्द पशु चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करें।

-केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आला अफसरों को दिए निर्देश

केंद्र ने एनएफएसएम का बदला नाम बीज उत्पादकों के लिए बढ़ाई सब्सिडी

» यह भी कहा-स्कीम का लाभ सिर्फ किसानों को मिलना तय किया जाए

» पारंपरिक-देशी बीज किस्मों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया प्रावधान

जागत गांव हमार, नई दिल्ली।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग से एक अहम बैठक ली, जिसमें समीक्षा करते हुए देश के किसानों के हित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के दिशा-निर्देशों में बड़े बदलाव करने की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटकों में किसानों हित में परिवर्तन किए गए हैं। मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए किसानों और बीज उत्पादकों के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई है। वहीं कृषि मंत्री ने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों से कहा कि योजना का लाभ सिर्फ किसानों को मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसानों के नाम पर अन्य कोई फायदा उठा लें। इस मिशन के तहत, पारंपरिक-देशी बीज किस्मों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है। वहीं पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण इकाई लगाने की भी शिवराज ने मंजूरी दी। शिवराज ने आला अफसरों को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होना चाहिए, ताकि किसानों का भला हो।

कृषि मंत्री ने दिए ये निर्देश

पूर्ववर्ती बीज और रोपण सामग्री उप मिशन सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन अब कृषि संवर्धन योजना का एक घटक होगा। मिशन के उद्देश्य है- देश के चिन्हित जिलों में सतत तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज (मक्क ा व जौ) और पोषक अनाज (श्रीअन्न) का उत्पादन बढ़ाना, व्यक्ति गत खेत स्तर पर मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बहाल करना, किसानों में विश्वास बहाल करने के लिए कृषि स्तरीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और कुशल बाजार संपर्कों के माध्यम से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए खेत पर फसलोपरांत मूल्य संवर्धन को बढ़ाना। बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) और किस्म प्रतिस्थापन दर (वीआरआर) को बढ़ाना और देश के बीज क्षेत्र के लिए इंफास्ट्रक्चर ढांचे में सुधार करना।

पारंपरिक किस्मों को मिलेगा बढ़ावा

पारंपरिक किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रावधान नए दिशा-निर्देशों में करने की स्वीकृति शिवराज सिंह ने दी है। क्योंकि ये पारंपरिक किस्में फसल विकास, स्थानीय अनुकूलन, पोषण मूल्य और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में रणनीतिक महत्व रखती हैं। इस प्रकार पहचान, सूचीकरण, उनके उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों की पहचान, जियोटैगिंग, उनके उत्पादन में वृद्धि, उनके उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और उनकी मार्केटिंग क्षमता बढ़ाने जैसे समग्र दृष्टिकोण के साथ पारंपरिक किस्मों को बढ़ावा देना अहम है। इसलिए, इस घटक में उनके बीज वितरण, उत्पादन, विभिन्न पहलुओं में क्षमता निर्माण, पीपीवीएफआरए और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत ऐसी किस्मों के बीज बैंक के निर्माण/विकास पर सहायता/प्रोत्साहन का प्रावधान है।

उच्च उपज किस्मों को प्राथमिकता

बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने नई प्रजातियों के प्रदर्शन, प्रमाणित बीज उत्पादन और प्रमाणित बीज वितरण के घटकों में किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की मंजूरी दी है। साथ ही जलवायु अनुकूल, बायो-फोर्टिफाइड और उच्च उपज देने वाली किस्मों के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी। मिशन के सभी प्रावधानों पर डिजिटली मानिटरिंग की जाएगी। कृषि मैपर और साथी पोर्टल की सहायता भी इसमें ली जाएगी।

पंचायतों में बनेंगे बीज प्रसंस्करण केंद्र

संशोधित दिशा-निर्देशों में ग्राम पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण इकाई का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत, एसएमएसपी के पूर्ववर्ती घटक अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण इकाई को पुनर्जीवित करने की स्वीकृति भी केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा दी गई है। ताकि देशभर के किसानों के आसपास के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर बीज प्रसंस्करण, सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण कार्य किया जा सके।

सहायता में भी वृद्धि

गैर पारंपरिक तरीके से आलू बीज उत्पादन के लिए नए घटक के निर्देशों को भी शिवराज ने मंजूरी दी है। वहीं बीज उत्पादन, विधायन, प्रमाणीकरण और टेस्टिंग से जुड़ी विभिन्न सरकारी एजेंसियों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की गई है, ताकि वे सशक्त होकर बेहतर कार्य कर सकें। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406

2. प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दड्ढद्धड्डद्यiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380

3. डा. वीरेन्द्र कुमार, प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304

4. डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncguptabau@gmail.com, मोबा- 8789708210

5. डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184

6. डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901

7. डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144

8. डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793

9. डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक, मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836

10. डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670

11. रोमा वर्मा, सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

नक्शा कार्यक्रम शहरी भूमि रिकार्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में लाएगा क्रांति

भोपाल

केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकार्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में क्रांति लाना है। साथ ही शहरी भूमि रिकार्ड्स के लिये एक सटीक और व्यापक भू-स्थानिक डाटाबेस तैयार करना है। यह कार्यक्रम हवाई और जमीनी सर्वेक्षणों को उन्नत जीआईएस तकनीक के साथ जुड़कर भूमि प्रशासन को बेहतर बनायेगा। संपत्ति स्वामित्व रिकार्ड्स को आसान करेगा और शहरी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा। सटीक भू-स्थानिक डेटा से निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होगी, भूमि उपयोग योजना अधिक प्रभावी बनेगी और संपत्ति से जुड़े लेन-देन आसानी से किये जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ड्रोन की उड़ान के साथ 18 फरवरी को रायसेन जिले से नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रदेश में वाटरशेड यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा भी कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः** अरविंद मिश्रा, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)